Vol 5 Issue 9 Oct 2015

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850

Impact Factor : 3.1560(UIF)
Volume - 5 | Issue - 9 | Oct - 2015

छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास एक अध्ययन

First Author Details :

एस. आर. ठाकुर
प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग

Co - Author Details :

सत्य प्रकाश मिश्रा
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छ. ग.)

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विकास के अध्ययन पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किये जा रहे है, जो राज्य के कृषि विकास के लिए उपयोगी हैं। सरकार के इन्ही प्रयासों का यह परिणाम है कि राज्य में कृषि में प्रगति दर्ज की गयी है। किन्तु राज्य शासन द्वारा कृषि विकास के क्षेत्र में जो प्रयास किये गये उसका कितना फायदा राज्य के कृषकों को प्राप्त हो रहा है, राज्य में कृषि विकास की वर्तमान स्थिति क्या हैं, प्रस्तुत शोध के द्वारा राज्य में कृषि विकास को रेखांकित किया गया है, शोध के निष्कर्ष मुख्यतः द्वितीयक समंकों के आधार पर प्रस्तुत किये गये है।

1 भूमिकाः

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के कृषि विकास एवं कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में धान का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है जिसके लिए इस राज्य को भारत सरकार द्वारा ''कृषि कर्मण'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कृषि यंत्र, सेवा केन्द्र की स्थापना, श्री पद्धति से धान उत्पादन, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम २००६ के अंतर्गत वन भूमि आबंटितों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं उर्वरक मिनि किट प्रदाय तथा भूमि सुधार हेतु हरी खाद का उपयोग आदि नवीन योजनायें प्रारंभ की गई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि लागत कम करने सहकारी बैंकों के माध्यम से १ प्रतिशत सालाना ब्याज में फसल ऋण, सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु रू. ७५०००/- अनुदान, सिंचाई पम्प में मीटर किराया एवं फिक्स चार्ज समाप्त करने का प्रावधान तथा ७०० नये उर्वरक गोदाम निर्माण की स्वीकृति जैसे योजनाओं को शामिल किया गया है।

2 प्रमुख उपलब्धियां

आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन :

फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में आधार/प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिये बीज उत्पादक कृषकों को अनुदान, नवीन बीज प्रक्रिया केन्द्रों की स्थापना, बीज गोदाम निर्माण कराने के फलस्वरूप प्रदेश में उच्चगुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन एवं उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका क–1

वर्ष	बीज उत्पादन (क्विंटल में)			प्रमाणीत बीज वितरण (क्विंटल में)		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
2003–04	32503	11954	44457	57319	15636	72955
2006–07	115079	9120	124199	109897	18146	128043
2011–12	610280	127553	737833	590290	102819	693109

राज्य में बीज उत्पादन की स्थिति

कृषि विभाग छ.ग. शासन

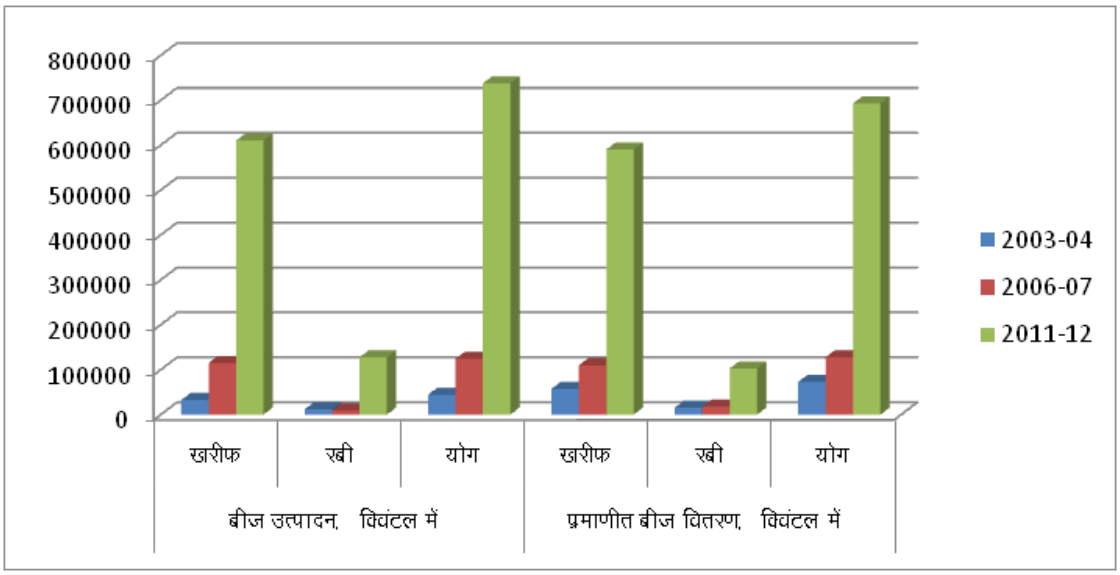

सिंचाई क्षेत्रों में विस्तार :

कृषि विकास के लिए सिंचाई साधन आवश्यक है। सिंचाई साधनों के अभाव में कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। अतः राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु-सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप निर्माण एवं पम्प स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई (नलकूप) योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। विगत वर्षों में २.६० लाख सिंचाई पम्पों को ऊर्जीकृत कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत विगत ०५ वर्षों में ३६५६७ नलकूप खनन एवं पम्प स्थापना तथा ३७३६ नवीन सिंचाई कूपों का निर्माण कर ६७६७२ सिंचाई पम्प पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना :

सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिस्टम की स्थापना हेतु केन्द्र पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना में लघु सीमांत कृषकों को देय ५० प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को ४० प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लघु सीमांत कृषकों को २५ प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को १० प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत अब तक २,३६,०६५ हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना की गई है।

फसल उत्पादन

राज्य शासन, कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका क–2
औसत वार्षिक विकास दर

विवरण	10 वीं पंचवर्षी योजना	11 वीं पंचवर्षी योजना
	2002–03 से 2006–07	2007–08 से 2010–11
चॉवल उत्पादन	1.50%	2.90%
दलहन	4.50%	7.40%
कुल खाद्यान	2.30%	3.50%

कृषि विभाग छ.ग. शासन

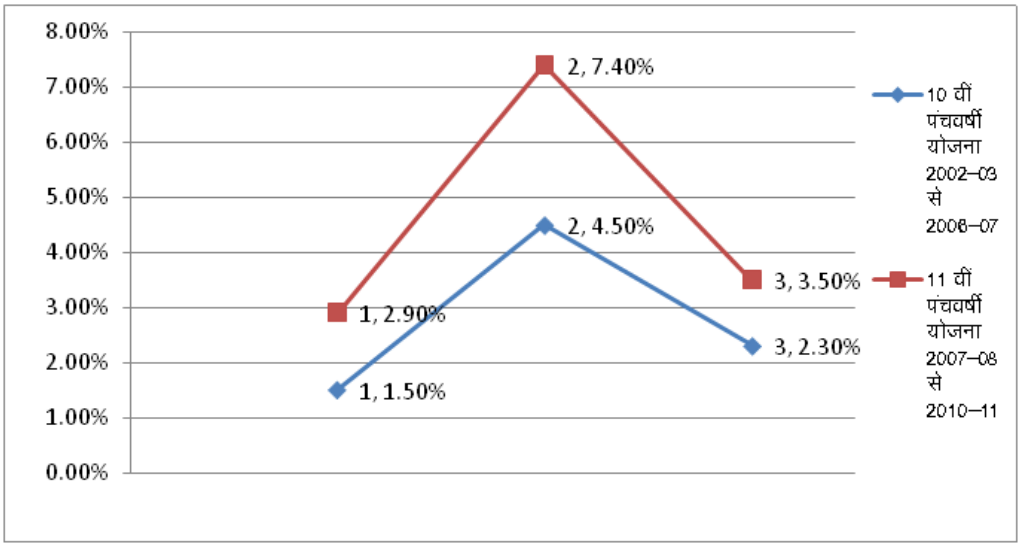

राज्य शासन की प्रमुख कृषकोन्मुखी नीतियां:–

१ चकबंदी के प्रयोजन से कृषकों को कृषि भूमि के अदला–बदली पर पंजीयन शुल्क मुक्त।
२ खलिहान अग्नि दुर्घटना राहत योजना अंतर्गत अधिकतम २५०००/–रूपये तक सहायता।
३ कृषकों को ५ हार्स पॉवर तक के सिंचाई पम्प पर ७५०० यूनिट तक बिजली मुफ्त।
४ समर्थन मूल्य पर कृषकों के धान खरीदी एवं तत्काल भुगतान की समुचित व्यवस्था।
५ समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी ।

कृषि में तकनीकों को प्रोत्साहन

प्रदेश में कृषि तकनीको/यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन द्वारा कृषकों के हित में केन्द्र प्रवर्तित मैक्रोमेनेजमेंट योजना अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्रों पर देय २५ प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त २५ प्रतिशत राज्य अनुदान दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा कृषि यंत्रों पर वाणिज्य कर समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्नत कृषि यंत्र किसी भी पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से क्रय करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

कृषकों को पॉवर टिलर, जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, रेज्ट शेड प्लांटर, शुगरकेन कटर प्लांटर, रिंग पिट डिगर/पोस्ट होल डिगर, रोटावेटर, स्ट्रारीपर, क्रॉप रीपर/बाइंडर, हैप्पी सीडर, वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर/न्यूमेटिक वेजिटेबल सीडर ४० प्रतिशत भारत सरकार एवं १० से २५ प्रतिशत राज्य शासन द्वारा देय अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि में मशीनों की बढ़ती हुई उपयोगिता तथा मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी विकासखंडों में न्यूनतम १ कृषि सेवा केन्द्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जनवरी २०१३ तक ७६ केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा ६७ केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगती पर है।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :

लाभप्रद एवं टिकाऊ खेती के लिये मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण एवं सुधार आवश्यक है किन्तु उचित फसल चक्र नहीं अपनाने तथा असंतुलित उर्वरक उपयोग के फलस्वरूप मृदा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है फलस्वरूप रासायनिक खाद के उपयोग के

बावजूद अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः राज्य शासन द्वारा भू-स्वास्थ्य सुधार हेतु हरी खाद, नाडेप/वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैस स्लरी एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा विभागीय योजनान्तर्गत कृषकों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त संतुलित उर्वरक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु खेतों के मिट्टी नमूनों का परीक्षण कर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों के उपयोग के लिए कृषकों को अनुशंसा देने हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्माण के समय प्रदेश में ०४ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित थे विगत ०३ वर्षों में ०४ नये स्थाई तथा ०४ चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित किया गया।

कृषि ऋण वितरण (सहकारिता क्षेत्र)

राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि ऋण में कई सहुलियतें प्रदान किया गया है। ऋण की उपलबधता को व्यापक किया गया है, ब्याज की दर को बहुत ही आसान किया गया है, कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का विकास किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से वितरित कृषि ऋण के ब्याज दर में निरंतर कमी उसे न्यूनतम कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में १ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन हेतु ऋण उपलब्ध।

कृषि के आधारभूत संरचना का विकास

राज्य शासन द्वारा कृषि विकास हेतु आवश्यक कृषि के आधारभूत संरचना यथा प्रशिक्षण केन्द्र प्रयोगशाला, बीज संसाधन केन्द्र एवं भंडार गृह आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य में कृषि विकास के लिए अधोसंरचना विकास हेतु जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए है वे निम्नलिखित हैं:-

- १ कृषकों एवं विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण।
- २ प्रक्षेत्र में ०६ बीज ग्रेडिंग मशीन की स्थापना।
- ३ ०३ नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण तथा ०१ निर्माणाधीन।
- ४ उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना।
- ५ कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला की सीापना
- ६ ३० बहुउद्देशीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, वर्तमान में बहुउद्देशीय कृषक ८३ निर्माणाधीन।
- ७ ८ शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में १०० मे.टन क्षमता के बीज गोदाम का निर्माण।
- ८ ३०८ सहकारी समितियों में १०० मे.टन क्षमता का गोदाम का निर्माण एवं २०२ निर्माणाधीन।
- ९ ९० कृषक सूचना केन्द्र का निर्माण।
- १० तीन नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण कार्य प्रगती पर है।

3 परिणाम

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के लिए राज्य शासन द्वारा योजना बद्ध रूप से प्रयास किया जा रहा है। कृषकों को राज्य शासन के प्रयासों से आसान किश्तों एवं न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषि में तकनीकों एवं मशीनों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे राज्य में कृषि का समुचित विकास हो सके। राज्य में कृषि कार्य में लगे लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किया गया है। विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य में कृषि विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का राज्य के कृषि विकास में योगदान है किन्तु अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१ भारतीय अर्थव्यवस्था - रूद्र दत्त सुंदरम।
२ छत्तीसगढ़ शासन आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष २०१३-१४।
३ प्रशासनिक प्रतिवेदन २०१२: छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़।
४ छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति : छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग।
५ वार्षिक रिपोर्ट २०१३ कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org